केवल वह 3 करोड़ रुपये था। आप लोगों के विलम्ब के कारण, निर्णय न लेने की क्षमता के कारण ये सारी गड़बड़ियां हो रही हैं और धीरे धीरे उसका इंस्टालेशन कास्ट बढ़ता जा रहा है। इसमें न ही हमारी राजस्थान सरकार का दोष है और न ही प्रकृति का दोष है, यह केवल आपके निर्णय न लेने की जो क्षमता है उसका दोष है। आप उसको इस तरह से नहीं छोड़ सकते हैं। मेरा दूसरा प्रश्न है कि आपने क्या इस बात का अंदाज किया है, एनेलिसिस और असेसमेंट किया है कि 7 करोड़ रुपया पर मेगावाट इसकी इंस्टालेशन कास्ट आने के बाद भी इसकी उत्पादन कास्ट कितनी आएगी। ऊर्जा की कास्ट आज जो हम थर्मल या हाइडिल से लेते हैं वह डेढ़ रुपये से दो रुपये पर यूनिट आती है क्या इससे भी ज्यादा इसकी कास्ट आएगी यह कृपा करके बताएं।

श्री कल्पनाथ राय : महोदय, मैंने आदरणीय अग्रवाल जी से निवेदन किया कि यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। सेंट्रल इलैक्ट्रिसिटी अथारिटी के पास में संशलेषण और विश्लेषण के लिये भेजा है... (**व्यवधान**)

श्री रामदास अग्रवाल : तीन साल में 90 करोड़ से 200 करोड़ रुपये उसकी कास्ट हो गयी है। अगर दो साल के बाद हम बात करेंगे तो ऐसा लगेगा कि इसकी इंस्टालेशन कास्ट... (**व्यवधान**) 16 करोड़ पर मेगावाट आयेगी। आज जल्दी क्यों नहीं करते। निर्णय लेकर जल्दी हां या ना का जवाब दीजिए... (**व्यवधान**) इसको खिले कर रहे हैं।

श्री सभापति : पहले उन्होंने ना किया था। फिर जब मुख्य मंत्री ने कहा फिर से विचार कीजिए तो फिर विचार कर रहे हैं।

श्री कल्पनाथ राय : सभापति महोदय, राजस्थान सरकार के प्रस्ताव को पुनः संशलेषण विश्लेषण के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथारिटी को भेज दिया गया है। उसके बाद आवश्यकतानुसार पी०आई०बी०, पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड में जाएगा। जब तक इसका टेक्नो इक्नामिकल क्लीयरेंस नहीं होगा तब तक भारत सरकार इसमें सहमति नहीं देगी... (**व्यवधान**) इसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन थर्मल से ज्यादा पड़ेगी ... (**व्यवधान**)... इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक टेक्नोइक्नामिक क्लीयरेंस नहीं हो जाएगा तब तक भारत सरकार का एप्रुवल इस पर नहीं हो सकता। फिर भी आपके शेखावत जी के अनुरोध पर यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और हम कोशिश करेंगे... (**व्यवधान**)...

श्री रामदास अग्रवाल मैं कास्ट आफ प्रोडक्शन पूछ रहा हूं कि थर्मल और सौर ऊर्जा के माध्यम से उत्पादन करने में कास्ट आफ प्रोडक्शन क्या आएगी। पर यूनिट क्या कास्ट आती है। आपने 7 करोड़ रुपया पर मेगावाट इंस्टालेशन कास्ट में लगा दिया लेकिन प्रोडक्शन कास्ट क्या आएगी यह तो बता दीजिए कृपा करके।

श्री कल्पनाथ राय : सभापति महोदय, अग्रवाल जी से मैंने निवेदन किया कि इसका टेक्नो-इक्नामिक कामर्शियल संशलेषण हो रहा है। इसके बाद ही मैं आपको बता पाउंगा।

श्री सभापति : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Retaliatory Trade Action Against India Under Special 301

*204. KUMARI SAYEEDA KHATUN :
SHRI BHUVNESH CHATURVEDI :

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether the US Administration have announced retaliatory trade action against India under the Special 301, withdrawing

the duty free Generalised System of Preference accorded to Indan pharmaceuticals imported into the United States;

(b) if so, what are the details thereof and what is Indian Government's reaction thereto;

(c) whether the issue has been taken up with the US Government; and

(d) if so, what is its response thereto?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) to (d) On the 29th of April the United States Government, in two separate actions:

(a) redesignated India as a priority foreign country under Special 301, and

(b) suspended duty free GSP treatment to 60 million dollars worth of Indian exports to the United States.

GSP treatment has been suspended mainly for pharmaceuticals, chemicals and allied products.

Government of India consider the US action untimely, unwarranted and unjustified. The views of Government of India have been conveyed to US officials. The US response is that the present decision could be reversed if India addresses US concerns on patent protection.

Pending proposals for development of tourism in Orissa

*206. SHRI PRAVAT KUMAR SAMANTARAY:

SHRI SARADA MOHANTY:

Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) what are the details of proposals which are pending with the Central Government for the development of tourism in Orissa; and

(b) since when these proposals have been pending and what are the reasons for delay in their approval?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI MADHAVRAO SCINDIA): (a) and (b) Out of the projects identified for Central financial assistance during 1991-92 only one proposal for the construction of Amenities Centre at Ratnagiri could not be sanctioned because of incomplete information from the State Government.

The State Government have been requested to furnish the requisite information.

Strike by Bank and Insurance Employees

*207. SHRI S. S. AHLUWALIA:
DR. BAPU KALDATE:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the employees of the Banking and Insurance institutions in the country went on a token strike on 30th April, 1992;

(b) if so, what issues were involved which led to the strike; and

(c) what steps have been taken by Government to resolve the issue?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DALBIR SINGH): (a) and (b) A section of employees in the Banking and Insurance institutions observed strike on 30th April, 1992 to press their demand for grant of pension as third retirement benefit.

(c) The profits of all the public sector banks for the year 1990-91 (latest available) were Rs. 371 crores only. It is estimated that the cost of conceding the demand of the bank employees for pension as a 3rd retirement benefit will be Rs. 200 crores per annum. This will have serious adverse effect on the health of the banking industry. The Indian Banks